लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

LEGISLATIVE BODIES SHOULD DISCUSS AND SHAPE SCHEMES FOR WELFARE OF THE LAST PERSON OF SOCIETY THROUGH USE OF TECHNOLOGY: LOK SABHA SPEAKER/तकनीक के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए विधायी संस्थाएं विभिन्न मंचों पर चर्चा करें और जनकल्याणकारी योजनाओं को आकार दें: लोक सभा अध्यक्ष

…

INDIA'S CONSTITUTION IS THE STRONGEST EXAMPLE OF SPIRIT OF INCLUSIVE GOVERNANCE: LOK SABHA SPEAKER/भारत का संविधान समावेशी शासन की भावना का सबसे सशक्त उदाहरण है: लोक सभा अध्यक्ष

…

LOK SABHA SPEAKER URGES LEGISLATIVE BODIES TO MAKE GOVERNANCE MORE RESPONSIBLE AND EFFICIENT BY ENSURING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF EXECUTIVE/लोक सभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने और शासन को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाए जाने का आग्रह किया

…

HISTORIC LEGISLATIONS PASSED BY PARLIAMENT OF INDIA HAVE ENHANCED PACE OF DEVELOPMENT AND MADE INDIA'S PROGRESS MORE INCLUSIVE: LOK SABHA SPEAKER/भारत की संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक क़ानूनों से विकास की गति तेज हुई है और भारत की प्रगति अधिक समावेशी हुई है: लोक सभा अध्यक्ष

…

BUILDING A SELF-RELIANT AND DEVELOPED INDIA WILL NOT BE POSSIBLE WITHOUT COOPERATION AND SUPPORT OF LEGISLATIVE INSTITUTIONS: LOK SABHA SPEAKER/विधायी संस्थाओं के सहयोग और समर्थन के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं: लोक सभा अध्यक्ष

…

LOK SABHA SPEAKER URGES LEGISLATIVE BODIES TO PLAY THEIR ROLES EFFECTIVELY BY INSTITUTIONALIZING RULES, BEST PRACTICES AND PROCESSES/लोक सभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों से नियमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप देकर अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का आग्रह किया

…

LOK SABHA SPEAKER CHAIRS PLENARY SESSION OF THE 10TH CPA INDIA REGION CONFERENCE/लोक सभा अध्यक्ष ने 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की

…

New Delhi; 23 September, 2024: Lok Sabha Speaker Shri Om Birla chaired the Plenary Session of the 10th Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region Conference in Parliament premises, New Delhi, today.

Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh and Presiding Officers of State Legislative Bodies of India participated in the Session.

The theme of the Plenary Session was, “The Role of Legislative Bodies in Attainment of Sustainable and Inclusive Development”.

Chairing the Session, Shri Birla emphasized on the use of technology to improve the efficiency and functioning of legislatures. He urged that legislative bodies should discuss on various platforms and shape welfare schemes for the welfare of the last person of the society through technology. He further added that in the current context, when technology and means of communication have become a part of people’s daily lives, public representatives should find ways and means to

meet the increasing aspirations and expectations of the people from democracy through legislative institutions.

Shri Birla noted that India’s constitution is the strongest example of the spirit of inclusive governance which inspires and guides us to move forward taking everyone along on the path of development. Stating that India's future lies in building a system in accordance with hopes and aspirations of the people, he noted that India can emerge as a model democratic nation through inclusive engagement and creation of a responsible system within the rapidly changing world. Emphasising that the role of legislative institutions is most important in achieving the goal of sustainable development and inclusive governance, Lok Sabha Speaker observed that democratic institutions, by ensuring accountability and transparency of the Executive, make the governance more responsible and efficient. It is the responsibility of public representatives and legislative bodies to come up with solutions to the challenges and obstacles on the path of inclusive development.

Stressing that India’s vision of inclusive development encompasses various aspects of development including good governance, social progress, economic development, and environmental sustainability, Shri Birla observed that the historic legislations passed by the Parliament of India have enhanced the pace of development in India and they have made India’s progress more inclusive, reaching to the last person in the row. Building a self-reliant and developed India will not be possible without cooperation and support of legislative institutions, noted Shri Birla. The legislature will be able to smoothly discharge the functions and duties necessary for sustainable and inclusive development where equal opportunities are available to all, all sections of the society have equal access to such opportunities and even the most vulnerable and deprived sections of the society are included in the journey of development. Shri Birla urged the Presiding Officers and legislators to reflect on the extent to which they had succeeded in fulfilling the expectations and aspirations of the people as the legislative body of the country in the journey of the last 7 decades. Without this introspection, the dream of inclusive development cannot be realized, he added.

Recalling that during the P-20 Summit, the Presiding Officers had emphasized the need to ensure a strength, sustainability, balance and inclusive development of nations and the role of legislatures in this process, Shri Birla opined that such a global order can be possible only when the necessary policies are made for this, there is a wide discussion on such policies by the public representatives, and their implementation is done through good governance. India with the philosophy of

‘Sarve Bhavantu Sukhinah’ and ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ has always been an advocate of this global order, noted Shri Birla.

Expressing hope that this Conference would give a new vision and direction to the Presiding Officers, he urged the participants to collectively work on the resolutions of sustainable development and inclusive welfare to success.

Earlier during the day, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla chaired the Executive Committee meeting of the Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region in Parliament House. In the meeting, Shri Birla emphasized on enhanced public participation in the democratic system. He suggested that Legislative Bodies must engage with Grass roots level bodies, especially the Panchayati Raj Institutions and by doing so, they would be discharging their responsibilities of fulfilling needs and aspirations of people more effectively. The Executive Committee held wide ranging discussions on agenda items.

नई दिल्ली; 23 सितंबर, 2024: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की।

राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश और भारत के राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने सत्र में भाग लिया।

पूर्ण अधिवेशन का विषय था, “सतत एवं समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका”।

सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री बिरला ने विधानमंडलों की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने आग्रह किया कि तकनीक के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए विधायी संस्थाएं विभिन्न मंचों पर चर्चा करें और जनकल्याणकारी योजनाओं को आकार दें। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जनप्रतिनिधियों को लोगों की लोकतंत्र से बढ़ती आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के तौर-तरीके और साधन विधायी संस्थाओं के माध्यम से खोजने चाहिए।

श्री बिरला ने कहा कि भारत का संविधान समावेशी शासन की भावना का सबसे सशक्त उदाहरण है, जो विकास के पथ पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य शासन व्यवस्था को जन-जन की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने से ही उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत समावेशी सहभागिता एवं उत्तरदायी शासनव्यवस्था के माध्यम से एक आदर्श लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि सतत विकास और समावेशी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधायी संस्थाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्यपालिका की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करके शासन को अधिक जिम्मेदार एवं कुशल बनाती हैं। समावेशी विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों एवं बाधाओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों एवं विधायी निकायों की जिम्मेदारी है।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के समावेशी विकास के विजन में सुशासन, सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं, श्री बिरला ने कहा कि भारत की संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कानूनों से भारत में विकास की गति तेज हुई है और इससे भारत की प्रगति और अधिक समावेशी हुई है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। श्री बिरला ने कहा कि विधायी संस्थाओं के सहयोग और समर्थन के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधायिका अपने कार्यों और कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करते हुए सतत और समावेशी विकास कर सकेगी, जिससे सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे, समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच होगी और समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग भी विकास की यात्रा में शामिल होंगे। श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों और विधायकों से आग्रह किया कि वे इस बात पर चिंतन करें कि पिछले 7 दशकों की यात्रा में देश के विधायी निकाय के रूप में वे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में कहाँ तक सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आत्ममंथन के बिना समावेशी विकास का सपना साकार नहीं हो सकता।

श्री बिरला ने इस बात का उल्लेख किया कि पी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने राष्ट्रों के सुदृढ़, स्थिर, संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता और इस प्रक्रिया में विधानमंडलों की भूमिका पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी वैश्विक व्यवस्था तभी संभव है जब इसके लिए अनुकूल आवश्यक नीतियां बनाई जाएं, जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी नीतियों पर व्यापक चर्चा की जाए और सुशासन के माध्यम से उनका क्रियान्वयन किया जाए। श्री बिरला ने कहा कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन के साथ भारत ने सदैव इस वैश्विक व्यवस्था का समर्थन किया है। यह आशा व्यक्त करते हुए कि इस सम्मेलन से पीठासीन अधिकारियों को एक नई दृष्टि और दिशा मिलेगी, श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से सामूहिक रूप से काम करते हुए सतत विकास और समावेशी कल्याण के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का आग्रह किया।

इससे पहले लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संसद भवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकारी समिति में श्री बिरला ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि विधायी निकायों को जमीनी स्तर के निकायों, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा करके वे लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। कार्यकारी समिति ने एजेंडा की मदों पर व्यापक चर्चा की।